

संपादकीय

राज्य में कार्यक्रमों और सांगठनिक गतिविधियों में तेजी

जनजोहार के इस अंक के प्रकाशित होने के दौरान ही किसानों और मजदूरों के दो महत्वपूर्ण संगठन झारखण्ड राज्य किसान सभा और सीटू का राज्य सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इन दोनों सम्मेलनों से मेहनतकशों के साझा संघर्ष को तेज करते हुए झारखण्ड में वर्गीय और जनआंदोलन को तीखा किये जाने का संकल्प लिया गया। इसी अवधि में छात्रों के संगठन एसएफआई का राज्यस्तरीय कन्वेंशन सम्पन्न हुआ जिसमें नई शिक्षा नीति के खिलाफ लगातार अभियान चलाने और राज्य के शैक्षणिक परिसरों में जनवादी छात्र आंदोलन गठित करने की दिशा में पहलकदमी किया गया। उसी तरह दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य कन्वेंशन से वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसी दौरान स्थानीय समस्याओं पर झारखण्ड के कई जिलों में आंदोलनात्मक कार्यक्रम किये गये जिसके अन्तर्गत धनबाद जिले के सुदामडीह में कोल वाशरी को चालू किये जाने की मांग को लेकर जुलूस और जनसभा आयोजित की गई जिसमें स्थानीय लोगों की अच्छी भागीदारी हुई और पार्टी का शाखा कार्यालय जो कि वर्षों से बंद पड़ा था उसे पुनः खोला गया।

नफरत की मुहिम के खिलाफ और सामाजिक सदभाव और एकजुटता के लिए जारी अभियान को और आगे बढ़ाते हुए संविधान दिवस के दिन एक प्रभावी गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। इसी क्रम में रांची में स्कूली बच्चों के बीच अंधविश्वास एवं नफरत के खिलाफ और संविधान के पक्ष में फिल्म शो का आयोजन जारी है। □



संयुक्त किसान मोर्चा का राजभवन के समक्ष प्रदर्शन



26 नवम्बर 2022 को किसान आंदोलन के दो साल पूरे होने और संविधान दिवस के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर किसानों के फसलों के लिए एम.एस.पी. का कानून बनाने, संपूर्ण झारखंड में सुखाड़ राहत चलाने, धान क्रय केंद्र खोलने, कर्ज माफी, वनपट्टा सहित किसान मुद्दों पर तथा मोदी सरकार के तीन माह के अन्दर एम.एस.पी. का कानून सहित अन्य मांगों पर लिखित आश्वासन देने के वावजूद 10 माह से ज्यादा बीतने पर झारखंड राजभवन के

समक्ष किसान मार्च निकालकर आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किया गया एवं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के नाम राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा गया।

झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुरजीत सिन्हा ने कहा कि ये मार्च मोदी सरकार को चेतावनी है कि एम.एस.पी. का कानून सहित किसानों की लंबित मांगों पूरी नहीं हुई तो देश भर के किसान 5 अप्रैल को दिल्ली कूच करेंगे।

अखिल भारतीय किसान सभा के

राज्य अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा अन्नदाता किसान ही मोदी सरकार के तानाशाही कदमों को रोक सकता है, एम.एस.पी. का कानून नहीं बना कर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। किसान संग्राम समिति के महासचिव राजेंद्र गोप ने कहा मोदी सरकार के किसानों के साथ विश्वासघात को देश की जनता देख रही है, गद्दी से बेदखल होना पड़ेगा, राजद किसान सेल के राज्य उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा किसान आन्दोलन के कारण तीनों काला कानून रद्द होना मोदी सरकार की करारी हार है। एआईकेएस महासचिव महेंद्र पाठक ने कहा मोदी सरकार घोर किसान विरोधी सरकार है, इसके आलावे किसान संग्राम समिति के लोदी मुंडा, झारखंड राज्य किसान सभा के बिरेंद्र कुमार आदि ने भी सभा को संबोधित किया। प्रदर्शन के पूर्व रांची रेलवे स्टेशन से मार्च करते हुए हजारों किसान राजभवन पहुंचे। राज्य किसान सभा अध्यक्ष सुफल महतो ने सभा की अध्यक्षता की। □

साझा मंच



गुलामी, लोकतंत्र, आजादी, संविधान और फिर लोकतान्त्रिक-गणतंत्र की हमारी यात्रा बेहद रोचक रही है। हजारों सालों से विभिन्न रियासतों में बटी निरीह, निरक्षर, कुपोषित-शोषित लगभग अधिकार विहीन प्रजा ने पहली बार 1946 में लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुना, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली, दिसंबर 1947 से संविधान सभा ने डॉ राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान बनाने का काम शुरू किया। डॉ भीम राव अंबेडकर संविधान ड्राफ्ट लेखन कमिटी के अध्यक्ष बने। 299 सदस्यीय संविधान सभा के दो साल 11 महीने और 18 दिनों की सामूहिक मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को देश और देशवासियों द्वारा स्वीकृत और अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक सार्वभौमिक लोकतान्त्रिक गणतंत्र बन गया। देशवासी पूरे इतिहास में पहली बार प्रजा से सर्वोच्च अधिकार

संपन्न नागरिक बने।

हजारों सालों से चले आ रहे असंख्य विधि के विधानों की जगह 1 प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 खंड और 8 अनुसूचियों से सुसज्जित भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। संविधान लागू करने के लिए संविधान के अनुरूप संवैधानिक संस्थान बने, योजनाएं बनीं, काम हुआ, जिससे बाद के कुछ वर्षों में देश और देशवासियों की दशा और दिशा में अकल्पनीय परिवर्तन आया। भारत विश्व के लिए बहुलता में एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समताएं सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम भारत के लोग की सर्वोच्च सार्वभौमिकता के साथ संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकारों से लैस देशवासियों ने अनेक सीमाओं और बाधाओं के बावजूद आधुनिक, सार्वभौमिक, प्रगतिशील, वैज्ञानिक चेतनायुक्त सामाज की मजबूत आधारशिला रखी जिसमें कालांतर में पंथ निरपेक्षता और समाजवादी प्रारूप

भी जुड़ा, और देश ने सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक क्षेत्र में पूरे इतिहास में तीव्रतम गति से प्रगति की।

पिछले 72 सालों से हमारा संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र का आधार है और संवैधानिक संस्थाएं इसको लगातार मजबूत करने के प्रमुख साधन हैं। एक तरफ देश को अराजकता से बचाते हुए और दूसरी तरफ सत्ता पर अंकुश रखते हुए संविधान के माध्यम से हम भारतीय देश की विकास यात्रा में कमोबेश सफल रहे हैं।

संविधान अक्षुण्ण भी नहीं है, इसमें 105 संशोधन भी हुए हैं। संविधान में कमियां भी हैं जो समय-समय पर इंगित भी होती हैं। देश की सर्वोच्च शक्ति संपन्न इकाई हम नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों से चूक रहे हैं किसका लाभ केंद्रीय सत्ता लेकर हमारे नागरिक अधिकारों पर लगातार हमला कर रही है।

सत्ता अपने ऊपर अंकुश नहीं चाहती। 1975 का आपातकाल, धारा 356 का अनुचित उपयोग, POTA, TADA, AFASFA और अब UAPA जैसे काले कानून और संवैधानिक संस्थाओं का लगातार क्षरण और उनका दुरुपयोग सत्ता में बैठे लोगों का प्रयास रहा है। पिछले आठ सालों में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

लोकतंत्र के नाम पर संविधान के मर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, गरिमा, समाजवाद, ... शेष पेज 3 पर

सीटू का 7वां राज्य सम्मेलन

(सीटू) का दो दिवसीय 7वां राज्य सम्मेलन रविवार को लौह नगरी जमशेदपुर में संपन्न हुआ। सम्मेलन के अंतिम दिन 51 सदस्यीय नई राज्य कमिटी और 34 सदस्यीय पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। जिसमें झारखंड

कमिटियों का पुनर्गठन करने, राज्य में बंद किए गए स्कूलों को पुनः खोलने, आंगनबाड़ी केन्द्रों की 10388 पोषण सखी को पुनः बहाल करने, सभी योजना कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी के लाभ के दायरे में लाने तथा भयानक महंगाई, बेरोजगारी,



सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण, मजदूर विरोधी लेबर कोड के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हुए सरकार की जन विरोधी व किसान-मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया

गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सीटू के अखिल भारतीय महासचिव ने संबोधित किया और समापन सत्र को अखिल भारतीय वरीय उपाध्यक्ष ज्ञान शंकर मजुमदार ने संबोधित किया। रिपोर्ट राज्य सचिव प्रकाश विप्लव और लेखा-जोखा कोषाध्यक्ष अनिर्वान बोस ने पेश किया। सम्मेलन में कोयला और इस्पात के अलावा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 16 उद्योगों के संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सीटू की 42 यूनिट के 372 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। □

कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष और झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु श्री शिवू सोरेन को सीटू झारखंड का मुख्य संरक्षक बनाया गया। इसके साथ मिथलेश सिंह अध्यक्ष, भवन सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, विश्वजीत देव महासचिव, आर. पी. सिंह अतिरिक्त महासचिव और अनिर्वान बोस कोषाध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्य स्थल में लाल झंडा फहराने, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने, झारखंड में न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण व श्रम विभाग की विभिन्न

संभावना है। उन्होंने शहर गांव में किसान सभा, हर किसान किसान सभा में के नारों के आधार पर हर गांवों में किसान सभा का निर्माण, एवं संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। तत्पश्चात झारखंड राज्य किसान की 35 सदस्यीय कमिटी निर्वाचित हुई। सुफल महतो अध्यक्ष, सुरजीत सिन्हा महासचिव और विवेन्द्र कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन में महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, विस्थापन, सुखाड़, किसान आत्महत्या पर प्रस्ताव पारित किए गए। □

झारखण्ड राज्य किसान सभा का 7 वां राज्य सम्मेलन संपन्न

झारखंड राज्य किसान सभा का 7 वां राज्य सम्मेलन सम्पन्न, सुफल महतो- राज्य अध्यक्ष, सुरजीत सिन्हा-महासचिव, विवेन्द्र कुमार- कोषाध्यक्ष चुने गए।

दिनांक 5- 6 नवम्बर 2022 को झारखंड राज्य किसान सभा का 7 वां राज्य सम्मेलन, राजेन्द्र सिंह मुंडा नगर, ज्योतिन

अप्रैल 2023 में देशव्यापी आंदोलन होगा। सम्मेलन का समापन वक्तव्य में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कृष्णा प्रसाद ने कहा कि झारखंड में जल, जंगल, जमीन, पलायन, विस्थापन, धान क्रय केंद्र मुद्दे पर आन्दोलन के आधार पर झारखंड में किसान सभा की प्रबल



सोरेन, विश्व देव सिंह मुंडा मंच - सोनाली मैरेज हाल, सिल्ली में सम्पन्न हुई। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढावले ने उद्घाटन करते हुए कहा 13 माह चले किसान आन्दोलन जिसमें 715 किसान शहीद हुए थे, मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून रद्द करना पड़ा। 3 माह के अन्दर एम.एस.पी. का कानून बनाने का लिखित आश्वासन लागू नहीं करना 90 करोड़ किसानों के साथ विश्वासघात है। 10 माह से ज्यादा समय बीत चुका है। ऐसे में देश भर में मार्च -

संभावना है। उन्होंने शहर गांव में किसान सभा, हर किसान किसान सभा में के नारों के आधार पर हर गांवों में किसान सभा का निर्माण, एवं संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। तत्पश्चात झारखंड राज्य किसान की 35 सदस्यीय कमिटी निर्वाचित हुई। सुफल महतो अध्यक्ष, सुरजीत सिन्हा महासचिव और विवेन्द्र कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन में महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, विस्थापन, सुखाड़, किसान आत्महत्या पर प्रस्ताव पारित किए गए। □

दलित शोषण मुक्ति मंच का राज्य कन्वेंशन



संविधान दिवस पर 26.10.2022 को झरिया में दलित शोषण मुक्ति मंच (डीएसएमएम) का दो दिवसीय राज्य कन्वेंशन हुआ। दिनेश रविदास के भारत का संविधान की प्रस्तावना पाठ से सभा शुरू हुई। मुख्य वक्ता डीएसएमएम के राष्ट्रीय सचिव नत्थू प्रसाद ने कहा कि हमारे पिछड़ेपन की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं जिसे जड़ से खत्म करना होगा। बाबा साहेब ने जितनी तकलीफ झेली, वे कितने बार मरते हैं, जिन्दा होते हैं, उसका हिसाब नहीं है। 2 अप्रैल 2018 को बिना किसी पार्टी के समर्थन से दलितों ने ऐतिहासिक भारत बंद किया था। संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसकी रक्षा करनी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये हमारी विरासत है,

उसी रास्ते पर हमें चलना होगा। सीटू झारखंड के सचिव संजय पासवान ने कहा कि आज निजीकरण के रास्ते आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, सरकारी नौकरी को समाप्त किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जा रही है और पिछले दरवाजे से संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है। इसलिए हमें संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। सभा को बामसेफ के एस एन तांती, बीएमपी के राजीव रंजन, युवा मोर्चा के शम्भु पासवान आदि ने मुख्य रूप से संबोधित किया। इस अवसर पर बालक सम्यक खातिकर ने बाबा साहेब और संविधान से संबंधित जनगीत गाकर उपस्थित लोगों को उत्साहित किया। सभा की अध्यक्षता शिव बालक पासवान ने की। शिव बालक पासवान अध्यक्ष, दिनेश रविदास सचिव और राम बालक धारी कोषाध्यक्ष चुने गए। □

गिग वर्कर्स की हड़ताल



रांची में जोमैटो के डिलीवरी ब्वाय (गिग वर्कर) जोमैटो प्रबंधन के खिलाफ श्रम भवन पहुंचे और जोमैटो प्रबंधन की वर्कर विरोधी रवैये पर हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। इसका नेतृत्व आल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन (सीटू) के महासचिव प्रतीक कुमार, सीटू के कोषाध्यक्ष अनिर्वान बोस, सुब्रत विश्वास और रोहित यादव ने किया। इस मामले में संयुक्त श्रमायुक्त द्वारा हस्तक्षेप किया गया और जोमैटो मैनेजमेंट को अगले 3 दिसम्बर तक गिग वर्कर्स के द्वारा उठाए गए मांगों पर त्रिपक्षीय वार्ता के लिए बुलाया है। संयुक्त श्रमायुक्त के आश्वासन पर यूनियन ने 15 नवंबर से घोषित राज्यव्यापी हड़ताल को तत्काल स्थगित करते हुए घोषणा की है कि यदि 3 दिसंबर तक उनकी न्यायोचित मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तब 4 दिसंबर से जोमैटो के सभी डिलीवरी ब्वाय हड़ताल पर चले जायेंगे। □

एसएफआई का राज्य स्तरीय कन्वेंशन



21.11.2022 को पाकुड़ में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) का राज्य स्तरीय कन्वेंशन सम्पन्न हुआ जिसमें पूरे राज्य से 90 छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एसएफआई की अखिल भारतीय संयुक्त सचिव दीप्तिता धर ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बोलते हुए शिक्षण संस्थानों में रिक्त स्थानों पर शिक्षकों की बहाली, शिक्षा के निजीकरण और संप्रदायीकरण पर रोक, मनमाने फीस वसूलने पर रोक की मांग सहित सभी को शिक्षा देने के लिए जीडीपी का 10% खर्च करने की मांग की। कन्वेंशन में 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मुनाजिर खान संयोजक, अरविंद और मुदस्सर शेख सह संयोजक सहित 15 सदस्यों का नव नेतृत्व निर्वाचित हुआ। कन्वेंशन से पहले सैकड़ों की संख्या में एक जुलूस राधाबगान से मुख्य सड़क होते हुए सिदो-कान्हू पार्क तक निकला। □

...साझा मंच

..... शेष पृष्ठ 1 का पंथ निरपेक्षता, सब पर हमला है। संगठित होने और विरोध करने के अधिकार पर भी हमला है।

एक महान नेता ने सच ही कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज की केंद्र सरकार संसद में सवाल नहीं सुनती, विरोध नहीं चाहती, ऐसा करने वालों को जेल में ठूस देती है। विरोध के स्वर को मुख्य मीडिया में भी स्थान नहीं मिलता। जनपक्षीय कानून बदले या निरस्त किए जा रहे हैं, अवैज्ञानिकता और अन्धविश्वास का प्रचार प्रसार हो रहा है, नागरिक अधिकारों का तेजी से क्षरण हो रहा है।

ऐसे समय में हम भारत के लोग अपनी नागरिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हजारों सालों के निरंकुश सत्ता की अधिकार विहीन प्रजा बनने के युग में नहीं लौट सकते। भारतीय

संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र के नागरिक बने रहने की कुंजी है और सत्ता पर अंकुश है।

26 नवंबर 2022 को स्थानीय रांची प्रेस क्लब सभागार में साझा मंच झारखंड (समझ) और रांची प्रेस क्लब ने संविधान दिवस पर “लोकतांत्रिक-गणतंत्र, संघीय प्रणाली और मौलिक अधिकार” विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें उपस्थित वक्ताओं ने संविधान बचाने, देश बचाने, नागरिकता बचाने के लिए संकल्प लिया।

देश भर में संविधान पर हमले का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों कर हैं। साझा मंच ने भी निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।

साझा मंच और प्रेस क्लब के सभी सदस्य अपने घरों में संविधान की प्रस्तावना को प्रमुख स्थान पर लगाएं और संविधान की प्रति रखें और उन्हें नियमित रूप से पढ़ें।

अपने संपर्कों को भी ऐसा

करने को लगातार प्रेरित करें और इस कड़ी को लगातार बढ़ाएं।

स्कूल-कॉलेजों और टोले-मुहल्लों में भी नियमित रूप से संविधान पर कार्यक्रम आयोजित करें।

साझा मंच आगामी 15 जनवरी तक राज्य के सभी जिलों में अपनी इकाई गठन कर समाज के साझा उद्देश्यों पर निरंतर कार्यक्रम आयोजित करे।

7 दिसंबर से 30 दिसंबर तक राज्य भर में एक संविधान सुदृढ़ीकरण जत्था का आयोजन किया जाए जो रांची से शुरू हो कर राज्य के 24 जिला होते हुए वापिस 31 दिसंबर को रांची पहुंचे। हर जिला जत्था रिसीव करे, जिले में दिन भर कार्यक्रम करे और अगले सुबह कार्यक्रम के अनुरूप निर्धारित जिले को जत्था सौंप दे।

30 जनवरी को रांची में संविधान और नागरिकता विषय पर एक विराट जन रैली का कार्यक्रम रखा जाए

जिसमें देश-राज्य के ख्याति प्राप्त वक्ताओं को आमंत्रित किया जाए।

एक कमिटी का गठन हो जो संक्षिप्त संविधान पर 30 पन्नों की एक पुस्तिका बनाए जिसे साझा मंच की ओर से प्रकाशित कर न्यूनतम मूल्य पर आम जन के बीच वितरित किया जाए।

गोष्ठी में संजय मिश्रा (संविधान का महत्व), समीर दास (संघीय प्रणाली), चंद्र भूषण चौधरी (आनुपातिक प्रतिनिधित्व), दीनानाथ (अंबेडकर और संविधान), एच बी सिंह (संविधान की संरचना), काशी नाथ चटर्जी (शिक्षा व्यवस्था का तीव्र विघटन), किरण जी और कुमुद जी (संविधान पर हमला), फरहान रहमान (संविधान और आशा) ने सक्रिय रूप से अपनी बातें रखी।

अमल पांडे ने संविधान की प्रस्तावना के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्यों पर अपने विचार के साथ गोष्ठी का संजय मिश्रा के साथ संचालन किया। □

अक्टूबर क्रांति दिवस



दुनिया की पहली समाजवादी क्रान्ति 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक पार्टी द्वारा कामरेड लेनिन के नेतृत्व में जारशाही के खिलाफ की गयी थी। यह दुनिया के इतिहास में एक युगांतरकारी घटनाक्रम था जिसने केवल मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का ही खात्मा नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया में औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को भी एक नयी दिशा दी। इसका प्रभाव हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ चल रहे आजादी के आंदोलन पर भी पड़ा। इस क्रान्ति ने प्रथम विश्व युद्ध में तबाह हुए रूस को सोवियत संघ के रूप में साम्राज्यवाद के खिलाफ तीसरी दुनिया के विकासशील देशों को उनके शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं सोवियत संघ ने भूख, बेरोजगारी और गरीबी का ही खात्मा नहीं

किया बल्कि द्वितीय विश्वयुद्ध में फासिज्म को पराजित करने में नेतृत्वकारी भी भूमिका अदा की और समाजवादी शिविर का निर्माण कर वैश्विक शक्ति संतुलन में युद्ध पिपासू अमरीकी दादागिरी को नियंत्रित किए जाने का काम किया। हालांकि कई कारकों के चलते समाजवाद का पराभव हो गया लेकिन पूरी दुनिया में वैज्ञानिक समाजवाद की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है क्योंकि विश्व पूंजीवाद केवल मुनाफे और शोषण की व्यवस्था है जो मनुष्य को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के साथ - साथ उसके सामुदायिक प्रगति के सारे दरवाजे बंद कर देती है। कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में वैज्ञानिक समाजवाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि शोषण मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके। अक्टूबर क्रांति की विरासत और स्मृति परिवर्तनकारी शक्तियों के लिए हमेशा प्रकाश स्तम्भ का काम करती रहेगी। □

डिलिस्टिंग के षडयंत्र का विरोध करो

माकपा आरएसएस प्रायोजित ‘जनजाति सुरक्षा मंच’ द्वारा मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबी आदिवासियों को डिलिस्टिंग द्वारा “अनुसूचित जनजाति” की सूची से बाहर किये जाने की मांग का कड़ा विरोध करती है। माकपा का मानना है कि भारत और विश्व में आदिवासी, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, एथनिक तौर पर वे आदिवासी ही रहते हैं। आदिवासियों के नैसर्गिक आदिवासियत को किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है जहां कोई भी किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म से परे आदिवासी को देश का मूल निवासी माना है।

रघुवर सरकार के सीएनटी और एसपीटी ऐक्ट में संशोधन पर मुँह की खाने के बाद भाजपा नीत केंद्र सरकार ने आदिवासियों के परंपरागत सरना कोड को मान्यता देने की जगह अपने हिन्दुत्व और हिंदू राष्ट्र के षडयंत्रकारी एजेंडा से मुस्लिम और ईसाइयों पर हमलावर है और अपनी अनुषंगी इकाई “जनजाति सुरक्षा मंच” को डिलिस्टिंग द्वारा नफरत और धर्म के नाम पर आदिवासी एकता को तोड़ने में लगा दिया है।

माकपा का मानना है कि डिलिस्टिंग से आदिवासी परिवार-समाज कमजोर होगा। आदिवासियों की एकता कमजोर होगी। उदाहरण के लिए झारखंड में कई ऐसे आदिवासी परिवार हैं, जहां एक भाई संवसार (सरना) है तो दूसरा भाई ईसाई है। यदि ईसाई भाई का डिलिस्टिंग किया जाता है तो वह परिवार बंटेगा।

धर्मान्तरित ईसाई आदिवासियों की जनसंख्या वर्तमान में कुल आदिवासी जनसंख्या का लगभग 14% है जिनकी दास सभी प्रशिक्षण शिविरों में मुख्य प्रशिक्षक थे। प्रकाश विप्लव राज्य सचिव और सुखनाथ लोहरा सचिवमंडल सदस्य तमाड़ प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक के रूप में मौजूद थे।

जमीन डिलिस्टिंग से स्वतः सामान्य हो जायेगी। जब झारखंड में छोटानागपुर टेनेंसी ऐक्ट और संताल परगना टेनेंसी ऐक्ट के रहते हुए भी, और इस तरह की तमाम बर्दशें के रहते हुए भी धड़ल्ले से आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, तो डिलिस्टिंग आदिवासियों के जमीन की और अधिक लूट को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके असर से पंचायत से लेकर विधान सभा और लोकसभा तक में आदिवासी सीटें घटेंगी। लिहाजा सरकार को आदिवासी कानूनों को कमजोर करने और आदिवासी के खिलाफ कानून बनाने में आसानी होगी। झारखंड में संविधान की पांचवीं अनुसूची की व्यवस्था पर ही खतरा उत्पन्न हो जायेगा। इसलिए देश की जनता को सभी जनजाति समूहों के साथ एकजुट हो कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पोषित जनजाति सुरक्षा मंच और भारतीय जनता पार्टी की इस विभाजनकारी डिलिस्टिंग की राजनीति को परास्त करना चाहिए।

साथ ही, आदिवासियों को अपने मूल मुद्दों- चाहे वह पेसा कानून को लागू करने, छोटानागपुर टेनेंसी ऐक्ट और संताल परगना टेनेंसी ऐक्ट को मजबूत करने, आदिवासियों की हड़पी जमीन की वापसी, दखल-दहानी का मामला, वनाधिकार कानून को लागू करने, सरना धर्म कोड को लागू कर धार्मिक अल्पसंख्यक में शामिल होने, सभी आदिवासी भाषाओं को मान्यता और संरक्षण देने, संविधान की पांचवीं अनुसूची को लागू करने, अनुसूचित क्षेत्रों में नगरीय निकाय के लिए पेसा के तर्ज पर मेसा कानून बनाने, विस्थापितों के पुनर्वास, पलायन को रोककर रोजगार सृजन, कॉरपोरेट लूट रोकने, और इन जैसे और मुद्दों पर एकजुट होकर संघर्ष तेज करना चाहिए। □

प्रशिक्षण शिविर में पार्टी कार्यक्रम, संविधान, पार्टी व जनसंगठन आदि के बारे में बुनियादी बातें रखी गई जिसमें चर्चा और सवाल-जवाब पर सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। □

पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम

पार्टी के 7वें कांफ्रेंस के फैसले के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों/लोकल कमिटियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस क्रम में पहला बड़ा प्रशिक्षण शिविर रांची जिले के तमाड़ में आयोजित किया गया जिसमें 250 पार्टी/एजी ग्रुप के सदस्यों ने भाग लिया। पूर्वी

सिंहभूम के बोड़ाम और बोकारो में ब्रांच सचिवों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी सदस्यों ने हिस्सा लिया। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में भी ब्रांच सचिवों का प्रशिक्षण शिविर लगा जिसमें लगभग सभी साथियों की पूरी भागीदारी रही। सचिवमंडल सदस्य समीर

चौपाल

"रमेश कितना नालायक निकला, सिंह जी का लाखों रुपया पॉलिटिक्स में डूबा दिया। सिंह जी की भी मति मारी गई थी जो बेटा को मुखिया बनाने चले थे। रिटायरमेंट वाला पैसा भी इसी में स्वाहा हो गया। अब विलाप कर रहे हैं। हमने चेताया था कि अभी घोर कलियुग चल रहा है, अभी शूनों का समय है। अब देखिए कृष्णा जीत गया ना! सब ने एकतरफा वोट दे दिया उसको", पंडित जी बोले जा रहे थे।

"तो क्या करते पंडित जी ? हमसे कृष्णा-त्रिश्ना की जी हजरी नहीं होगी! जिसका सामने बैठने की औकात नहीं, उसको माथा पर कैसे बिठाते? हमारे पूर्वज हमको कभी माफ करते", सिंह जी बैठते हुए बोले!

"अब तो कृष्णा मुखिया बन गया! लेकिन बिना हमलोग के डायरेक्सन के वो क्या कर सकेगा? पॉलिटिक्स का 'प' भी उसको नहीं आता। अब हमलोग उसको बताएंगे पॉलिटिक्स कितनी कुत्ती चीज है। ऐसा चक्कर-धिन्नी में उसको फँसाएंगे ना कि नाम उसका रहेगा और काम सब हमलोगों को मिलेगा", साहूजी चहकें। यहाँ साहूजी, कुछ

किया जाए, छोड़ना तो नहीं है", पंडित जी बोले। सिंह जी की भी सहमति थी। सब चौपाल की ओर चल पड़े, आज कृष्णा का सम्मान हो रहा था वहाँ।

"नमस्कार! मैं आप सब का कृष्णा, अपने आपको आपकी सेवा में सपरिपत करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ कुछ माँगना चाहता हूँ! (तालियाँ) तालियाँ किसलिए, अभी मैंने किया ही क्या है? होश सम्भालने के बाद से ही वर्जनाओं से दो-चार होता रहा हूँ। ये मत करो, वहाँ मत जाओ, इनके पैर पड़े, वहाँ हाथ जोड़े खड़ा रहना आदि। बचपन गँवाना, धूप में देह तपाना, स्वास्थ्य लुटाना, कामचलाऊ शिक्षा पाना, भोजन कमाना आदि ही मेरी नियति थी। धर्म साफ-सफाई और दक्षिणा देने तक सीमित था तो राजनीति बड़ों के कहे अनुसार वोट देने तक सीमित! "बड़ों" के दिए संस्कार और विचार से परे सोचना भी अपराध जैसा था", कृष्णा का स्वर तल्ल था।

"संविधान ने कुछ बदलाव दिए लेकिन विभेदकामी सोच की खाई बनी रही। एक खतरनाक वृत्ति सामने आई, राजनीति बेकार है, राजनीति से दूर रहो! ये जम कर प्रचारित भी किया गया। ये सचमुच बहुत खतरनाक है। अच्छे लोग राजनीति से दूर हो गए और सत्ता लोभी राजनीतिक दलों की

गिरोहबंदी शुरू हुई जो अब चरम पर है और हमारे लोकतंत्र के लिए ही खतरा बन चुकी है! और तुरा ये है कि राजनीति को ही इसके लिए दोषी भी ठहराया जा रहा है", कृष्णा का स्वर संयत था।

"मैं चाहता हूँ कि हम सब राजनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और क्यूँ नहीं? आखिर, राजनीति है क्या? राजनीति दो शब्दों से बना है राज और नीति। राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने का तौर-तरीका। आप सोचिए, बिना अनुशासन और उचित नीतियों के कार्यान्वयन के क्या व्यक्तिगत प्रगति संभव है? क्या कोई परिवार बिना सही नीतियों के आगे बढ़ सकता है और क्या आप सब हमारे समाज को सुशासन, सही नीतियों और अपनी सक्रिय सहभागिता के बिना बदल सकते हैं? बिलकुल नहीं! यही देश और विश्व पर भी लागू होता है", कृष्णा उपस्थित जनो से मुखातिब था।

सत्ता लोभी राजनीतिक गिरोह, जिनको हमसे हमारे वोट के सिवा और कोई मतलब नहीं, हमारे मुँह तय करते हैं उम्मीदवार थोपते हैं, हमारे विरुद्ध ही नीतियाँ बनाते हैं और अपना कुशासन और कुव्यवस्था हम पर थोपते हैं। हमारे मुँह, हमारी समस्याएँ, हमारे सवाल,

और खुद हमलोग उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। झूठे वादे, झूठे सपने, आरोप-प्रत्यारोप और अनर्गल मुद्दों पर भावनात्मक चक्रव्यूह रच कर धर्म-जाति-वर्ग आदि में हमें बुरी तरह से बाँट कर ये हमारा वोट और हमारे सपने, दोनों छीन लेते हैं! और हम राजनीति को गाली देकर इनके लिए मैदान खाली कर देते हैं। नतीजा इनकी लगातार दीवाली और अपना लगातार दिवाला! ये लोकतंत्र की वास्तविक अवधारणा 'जनता का जनता द्वारा जनता के लिए' के बिलकुल विपरीत है! जनता का राजनीति से बढ़ता ये दुराव हमारी बदतर होती स्थिति और शासन की बढ़ती निरंकुशता का मुख्य कारण होता है। अतः मेरा आप सब से करबद्ध निवेदन है कि शोषण-अस्पृश्यता का खात्मा करने और मुझ तक को निरंकुश बनने से बचाने के लिए राजनीति को अपने जीवन में हर स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुद्दों के चयन और योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय सहभागिता रखें और व्यवस्था पर अंकुश रखें। एक नागरिक के तौर पर ये आपका प्रमुख संवैधानिक दायित्व भी है", कृष्णा हाथ जोड़े खड़ा था।

साहू जी के तोते उड़ चुके थे, सिंह जी मायूस थे, पंडित जी बुदबुदा रहे थे... 'घोर कलियुग है'। □

तस्वीरों में गतिविधियां ...



प्रशिक्षण शिविर तमाड़



प्रशिक्षण शिविर बोड़ाम



सुदामडीह में पार्टी कार्यालय की पुर्नस्थापना



बेफी सम्मेलन, हजारीबाग



प्रशिक्षण शिविर बहरागोड़ा



एड़वा का संविधान दिवस पर शपथ



एसएफआई सम्मेलन, पाकुड़



आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ रैली



ट्रेड यूनियन संयुक्त मंच की रांची रैली



सुदामडीह लाल मैदान से रैली निकाली गई।

पार्टी कोष में सहयोग की अपील

संघर्ष कोष के लिये स्वेच्छा से निम्नलिखित बैंक खाते में अपना योगदान करें।
Communist Party of India Marxist
Bank : Bank of Baroda
Main Branch, Ranchi
A/c No. : 0017020000219
IFSC Code : BARB0RANCHI